कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में प्राथमिक कृषि ऋण समितियां

संजय कुमार राकेश

ग्रामीण भारत के लिए प्राथमिक कृषि ऋण समितियों *'पैक्स'* का कॉमन सर्विस सेंटर ढांचे में समेकन एक क्रांतिकारी बदलाव है। सीएससी में परिवर्तित होकर, 'पैक्स' केवल कृषि ऋण प्रदान करने तक सीमित नहीं रह जाते, बल्कि अनेक सेवाओं के लिए एक समग्र केंद्र बन जाते हैं।

प्राथमिक कृषि ऋण समितियां *'पैक्स'* ग्रामीण भारत की कृषि अर्थव्यवस्था की आधारशिला रही हैं, जो दशकों से किसानों को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करती आ रही हैं। देश भर में 1 लाख से अधिक *'पैक्स'* फैले हुए हैं, जो विश्व के सबसे बड़े सहकारी नेटवर्क में से एक है और ग्रामीण जीवन के ताने-बाने में गहराई से जुड़े हुए हैं। हालांकि, ग्रामीण भारत की आवश्यकताएं बदल गई हैं, जो अब केवल कृषि ऋण तक सीमित नहीं रहकर अधिक व्यापक और सुलभ सेवाओं की मांग करता है। इसे समझते हुए सरकार ने *'पैक्स'* को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में पुनः परिकल्पित किया है, जिससे वे बहु-कार्यात्मक केंद्र बन गए हैं जो विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं। इस परिवर्तन का उद्देश्य ग्रामीण-शहरी अंतर को कम करना है ताकि डिजिटल और गैर-डिजिटल दोनों तरह की सेवाएं ग्रामीण नागरिकों को आसानी से उपलब्ध हो सकें, जिससे समुदाय सशक्त बने और समावेशी विकास को बढ़ावा मिले।

प्राथमिक कृषि ऋण समितियां देश के हर कोने में फैली हुई हैं और इनके पास 13 करोड़ से अधिक किसानों का विशाल सदस्य आधार है। उनकी व्यापक पहुँच को देखते हुए, वे डिजिटल सेवा पोर्टल पर सूचीबद्ध 300 से अधिक ई-सेवाओं को ग्रामीण नागरिकों तक पहुँचाने का प्रभावी माध्यम बन सकते हैं।

इस संदर्भ में 2 फरवरी, 2023 को सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज़ इंडिया लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे *'पैक्स'* को देशभर में ग्रामीण नागरिकों को सीएससी सेवाएं प्रदान करने का अधिकार मिला। इन सेवाओं में बैंकिंग, बीमा, निवेशक जागरूकता, कानूनी साक्षरता, आधार अपडेशन, ई-कॉमर्स, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आईआरसीटीसी, बस/हवाई टिकट, स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि इनपुट आदि शामिल हैं।

ग्रामीण विकास के लिए एक नया दृष्टिकोण

'पैक्स' का सीएससी ढांचे में समेकन ग्रामीण भारत के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव साबित हो रहा है। सीएससी में परिवर्तित होकर, *'पैक्स'* अब केवल कृषि ऋण प्रदान करने तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि अनेक सेवाओं के लिए एक 'संपूर्ण केंद्र' बन गए हैं। इन सेवाओं में आधार अपडेशन और पैन कार्ड आवेदन, सरकारी कल्याण योजनाओं के पंजीकरण की सुविधा और डिजिटल लेन-देन को सक्षम बनाना शामिल है। इसके अलावा, ये केंद्र ई-कॉमर्स गतिविधियों का समर्थन करते हैं, जिससे ग्रामीण निवासी ऑनलाइन वस्तुएं खरीद सकते हैं या अपने उत्पाद बेच भी सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं जैसे टेलीमेडिसिन परामर्श और दवाओं का वितरण भी उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को दूर किया जा सके । साथ ही, *'पैक्स'-सीएससी* शिक्षा और कौशल विकास के मंच भी हैं, जो ऑनलाइन पाठ्यक्रमों और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों तक पहुँच प्रदान करते हैं। यह व्यापक दृष्टिकोण ग्रामीण नागरिकों को आवश्यक सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराता है, जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होता है।

कृषकों को 'ऋण' से परे 'सशक्त' बनाना

'पैक्स' के सीएससी में परिवर्तन से किसानों को अत्यधिक लाभ होगा। पारंपरिक रूप से वित्तीय सहायता प्राप्त करने या अपनी उपज बेचने के लिए मध्यस्थों पर निर्भर किसानों को अब अपने स्थानीय *'पैक्स'* के माध्यम से सीधे बाज़ारों और सरकारी योजनाओं से जुड़ने का अवसर मिलता है। इससे मध्यस्थों की भूमिका समाप्त हो जाती है और किसान अपनी आय का अधिक हिस्सा सीधे प्राप्त कर पाते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुँच के साथ, वे अपनी उपज को सीधे खरीदारों तक पहुँचा सकते हैं, जिससे आपूर्ति श्रृंखला की पारंपरिक अड़चनों से बचा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, *'पैक्स'-सीएससी* किसानों को सर्वोत्तम कृषि

लेखक सीएससी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।

प्रथाओं, मौसम पूर्वानुमान और सरकारी सब्सिडी जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराते हैं, जिससे वे सूझ-बूझ से निर्णय ले सकते हैं। ये केंद्र प्रशिक्षण कार्यक्रम और उन्नत उपकरण उपलब्ध कराकर आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने को भी प्रोत्साहित करते हैं।

ग्रामीण उद्यमशीलता को बढ़ावा

'पैक्स' का सीएससी में परिवर्तन ग्रामीण उद्यमशीलता के नए अवसर भी खोलता है। ये केंद्र छोटे स्तर के उद्यमियों और कारीगरों के लिए वित्तीय सहायता और तकनीकी मार्गदर्शन के साथ-साथ बाज़ार से जोड़ने का काम भी करते हैं। ग्रामीण उद्यम 'पैक्स'-सीएससी के माध्यम से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपने उत्पाद बेच सकते हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं, और अपने उद्यम को बढ़ाने के लिए सूक्ष्म ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं। उद्यमशीलता पर यह ज़ोर स्थानीय रोज़गार के अवसर उत्पन्न करता है, जिससे ग्रामीण लोगों की शहरी प्रवास पर निर्भरता कम होती है। विशेष रूप से महिलाएं और युवा, जो कौशल विकास पहलों के ज़रिए व्यापार के अवसर तलाशने और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, इसका बड़ा लाभ उठाते हैं।

'पैक्स'-सीएससी के माध्यम से ग्रामीण अवसंरचना का सशक्तीकरण

'पैक्स' को सीएससी में बदलने के लिए मज़बूत अवसंरचना विकास की आवश्यकता होती है। इसमें अतिरिक्त सेवाओं के लिए *'पैक्स'* की भौतिक सुविधाओं का उन्नयन, दूरदराज़ के इलाकों में विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना, और प्रभावी सेवा वितरण के लिए आधुनिक आईटी सिस्टम लागू करना शामिल है। संचालन के डिजिटलीकरण में निवेश सेवा वितरण को अधिक पारदर्शी और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाता है, जिससे ग्रामीण समुदायों में विश्वास बढ़ता है। इसके अलावा, *'पैक्स'* कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम उन्हें इन उन्नत प्रणालियों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने में सक्षम बनाते हैं, जिससे सीएससी का सुचारू संचालन सुनिश्चित होता है। अवसंरचना विकास की प्रक्रिया निर्माण, आईटी और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर भी पैदा करती है, जो ग्रामीण आर्थिक विकास में योगदान देती है।

वित्तीय समावेशन को बढ़ावा

'पैक्स' को सीएससी में बदलने का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। कई ग्रामीण परिवार अभी भी औपचारिक बैंकिंग प्रणाली तक पहुँच से वंचित हैं। 'पैक्स'-सीएससी बैंकिंग सेवाएं जैसे खाता खोलना, जमा, निकासी और सरकारी सब्सिडी तक पहुँच प्रदान करके इस समस्या को दूर करते हैं। ये केंद्र ग्रामीण निवासियों को बीमा, पेंशन और बचत योजनाओं जैसे वित्तीय उत्पादों के बारे में भी शिक्षित करते हैं, जिससे वित्तीय साक्षरता की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। ग्रामीण परिवारों को उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम बनाकर, 'पैक्स'-सीएससी आर्थिक असुरक्षा को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ समन्वय

'पैक्स'-सीएससी पहल कई राष्ट्रीय कार्यक्रमों जैसे *डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया* और *आत्मनिर्भर भारत* के साथ पूरी तरह मेल खाती है। यह *डिजिटल इंडिया* मिशन का समर्थन करती है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देती है। *मेक इन इंडिया* अभियान के तहत यह ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहित करती है और स्थानीय उद्यमियों का सहयोग करती है। अंततः यह *आत्मनिर्भर भारत* के विज़न के अनुरूप है, जो स्थानीय रोज़गार के अवसरों और आर्थिक सशक्तीकरण के माध्यम से स्वावलंबी समुदाय बनाता है। इन उद्देश्यों के सामंजस्य के माध्यम से, 'पैक्स'-सीएससी समावेशी और सतत विकास प्राप्त करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करते हैं।

चुनौतियों को पार करना

हालांकि 'पैक्स'-सीएससी की संभावनाएं अपार हैं, तथापि इस पहल को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। ग्रामीण जनसंख्या में डिजिटल साक्षरता अभी भी कम है, जो सेवाओं के प्रभावी उपयोग में बाधा बनती है विशेषकर दूरदराज़ क्षेत्रों में अवसंरचना की कमी सहज सेवा वितरण में अड़चन पैदा करती है। पारंपरिक *'पैक्स'* कर्मचारियों में बदलाव के प्रति विरोध भी नई प्रक्रियाओं और तकनीकों को अपनाने में धीमापन लाता है। इन चुनौतियों का समाधान एक सामूहिक प्रयास से संभव है, जिसमें सरकारी एजेंसियां, सहकारिता संस्थाएं और निजी क्षेत्र के साझेदार शामिल हों। जन जागरूकता अभियान, अवसंरचना विकास के लिए सब्सिडी, और लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम इन बाधाओं को दूर करने और पहल की सफलता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं।

प्रमुख उपलब्धियां और प्रगति

30 अप्रैल 2025 तक, देश के 33 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 45,319 *'पैक्स'* ने सीएससी सेवाएं प्रदान करना शुरू कर दिया है। इन *'पैक्स'* के माध्यम से 85.70 करोड़ रुपये के लेन-देन हुए हैं। *'पैक्स'* कंप्यूटरीकरण के राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर के साथ सीएससी को जोड़ने का कार्य भी प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त, नेशनल काउंसिल फॉर कोऑपरेटिव ट्रेनिंग (NCCT) ग्रामीण नागरिकों को 300 से अधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए देशभर के *'पैक्स'* को प्रशिक्षण देने हेतु कार्यशालाएं आयोजित कर रहा है। यह पहल न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में आम नागरिकों को विभिन्न ई-सेवाओं की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करेगी, बल्कि *'पैक्स'* को स्थानीय स्तर पर विभिन्न नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए नोडल केंद्रों के रूप में भी परिवर्तित करेगी। इससे उनकी व्यापारिक गतिविधियों में विविधता आएगी, जिससे उनकी आय के स्रोत बढ़ेंगे और वे आर्थिक रूप से स्वावलंबी संस्थाएं बन सकेंगे। साथ ही, यह पहल देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर भी उत्पन्न करेगी। ❑